ASC-DPS/6.00/2Y

**डॉ. सुशील गुप्ता (क्रमागत) :** परन्तु उस बीमा पॉलिसी के लिए हेल्थ केयर सेन्टर्स कहां हैं? दिल्ली सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक खोले, लेकिन वह केवल 158 मोहल्ला क्लिनिक ही खोल पाई, क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय ने permission न देकर, उसको अटका दिया। मैं यूएनओ का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उसने मोहल्ला क्लिनिक योजना को एप्रिशिएट किया। मैं आज वित्त मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने वेलनेस सेन्टर के नाम पर मोहल्ला क्लिनिक की नकल की और मोहल्ला सेन्टर के नाम से पूरे हिन्दुस्तान में मोहल्ला क्लिनिक खोलना तय किया। मैं इसके लिए इनको धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि आप जो यह बीमा योजना ला रहे हैं, इसकी बजाय दिल्ली सरकार ने जो नियम अपनाया है कि गरीब रोगी, जो महीनों तक व सालों तक सरकारी हॉस्पिटलों में नम्बर न आने की वजह से अपना ऑपरेशन नहीं करा पाता, तो दिल्ली सरकार एक महीने के बाद उनके ऑपरेशन के पैसे स्वयं देती है। भारत सरकार भी ऐसे गरीब रोगियों के इलाज के लिए स्वयं पैसे दे और उनका प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाए। यानी बीमा कम्पनियों को पैसा देने के बजाय गरीब व्यक्ति का सीधा इलाज हो और वह प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर जाए। मैं कहना चाहता हूं कि अरविन्द केजरीवाल जी ने जो हार्ट केयर सिस्टम दिल्ली के अंदर चलाया है, उसके तहत मोहल्ला क्लिनिक के अंदर 100 से अधिक किस्म की दवाइयां, दो सौ से अधिक किस्म के टेस्ट मुफ्त किए जाते हैं। मैं आप से भी निवेदन करता हूं कि जो आप वेलनेस सेन्टर्स बना रहे हैं, उनके अंदर भी इसी प्रकार

की योजनाएं लाएं, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति अपने घर के नजदीक, जो प्राइमरी हेल्थ सेन्टर्स आपको बनाने चाहिए थे, उनको नहीं बनाया तो, उनके अंदर जाकर अपना इलाज करा सके।

मैं इसके साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूं कि देश की आजादी को 70 वर्ष हो चुके हैं। हिन्दुस्तान के संविधान को लागू हुए 68 वर्ष हो सकते हैं, हमारे संविधान के पहले पृष्ठ पर लिखा है कि हिन्दुस्तान सम्प्रभुता सम्पन्न देश, जिसमें पंथनिरपेक्ष समाज को धार्मिक समानता होगी। मैं कहता हूं कि आज भी देश की महिलाओं को साढ़े छः बजे के बाद घर से निकलने से पहले सोचना पड़ता है कि घर से निकलूं या न निकलूं, तो इस देश की सरकार ने कैसी समानता दी है? आज भी सदन के अंदर और सदन के बाहर महिलाओं का उपहास किया जाता है, तो फिर कैसी समानता देश के संविधान निर्माताओं ने दी है? मैं कहना चाहता हूं कि आज भी देश के बॉर्डर पर सैनिक मरता है, हम चुनाव के समय कहते हैं कि हम एक के बदले दस सिर लेकर आएंगे, जबकि वास्तविक स्थिति इसके विपरीत होती है, हमने उनकी रक्षा के लिए क्या कुछ किया है? क्या हमने उनके लिए कोई ठोस नीति बनाई है? मैं यह कहना चाहता हूं कि इसका एक सुगम तरीका है कि आप हिन्दुस्तान को शिक्षित करें और शिक्षा के ऊपर अधिक से अधिक बजट लगाएं।

महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान सरकार का जो शिक्षा के ऊपर बजट है, उसमें वह 2013-14 में साढ़े चार प्रतिशत था, जो 2016-17 में घटकर 3.65 प्रतिशत रह गया। 2017-18 में यह 3.71 परसेंट हो गया और इस बजट में आपने साढ़े तीन

परसेंट का प्रोविज़न रखा है। इसके विपरीत दिल्ली सरकार ने अपना बजट 24 परसेंट शिक्षा के ऊपर रखा है।

मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा और चिकित्सा एक ऐसा माध्यम है, जो हिन्दुस्तान के सौ परसेंट लोगों के काम आता है। हिन्दुस्तान काको बजट ऐसा नहीं बनना चाहिए कि पांच या दस परसेंट चन्द अमीर लोग उसके ऊपर निर्भर होकर देश की सारी सम्पत्ति को खा जाएं। आज 68 वर्ष बाद भी कैसी समानता सरकारें दे रही हैं? 2016-17 के अंदर देश का 53 परसेंट पैसा कुल मिलाकर एक प्रतिशत से कम लोगों के पास था, लेकिन जो 2017- 2018 के अंदर बढ़कर 73 परसेंट पैसा एक परसेंट लोगों के पास चला गया। आप लोग संविधान के दायरे में यह कैसी समानता लाना चाहते हैं? मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार चाहे कोई भी आए, पार्टी चाहे कोई भी आए, परन्तु देशहित सबसे ऊपर होना चाहिए। अगर आपको देशहित सबसे ऊपर लाना है, तो शिक्षा को ऊपर लाना पड़ेगा और हिन्दुस्तान को शिक्षित करना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार का शिक्षा के ऊपर साढ़े तीन परसेंट बजट है, आप उसको बढ़ाकर दिल्ली सरकार की तरह 24 परसेंट कीजिए। पूरे हिन्दुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर की ये शिक्षित हिन्दुस्तान के नौजवान अपने आप तकदीर बदल देंगे और, हम अपने आप दुनिया के पहले नम्बर पर जाएंगे, फिर हिन्दुस्तान को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि आज भी आप हिन्दुस्तान सरकार के राइट टू एजुकेशन एक्ट को देखिए, हर एक किलोमीटर के ऊपर प्राइमरी स्कूल होना

चाहिए और हर तीन किलोमीटर के ऊपर एक मिडिल स्कूल होना चाहिए। आज भी बीस-बीस, पच्चीस-पच्चीस किलोमीटर पर स्कूल नहीं है।

(2Z/LP पर जारी)

LP-KSK/6.05/2Z

**डा. सुशील गुप्ता (क्रमागत) :** क्या हम इस देश के अंदर ऐसी स्थिति लाना चाहते हैं? अगर यह आर्थिक असमानता रही, शिक्षा का अभाव रहा, तो वह दिन दूर नहीं, जब इस देश के अंदर अपराध बढ़ेंगे, इस देश के अंदर गरीब लोग अमीर लोगों को लूटकर खाएंगे और यही कारण है कि असंतोष है। आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि हज़ारों अमीर लोग, जो करोड़पति और अरबपति थे, वे हिंदुस्तान छोड़कर जा रहे हैं। हिंदुस्तान का पैसा - क्या सरकार ने कभी यह सोचा है कि ये लोग क्यों जा रहे हैं? हिंदुस्तान का यह पैसा कहाँ जा रहा है, किस रास्ते से जा रहा है? क्या आपने कभी उसको रोकने का प्रयत्न किया? मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि शिक्षा के नाम पर आज भी सब कुछ ठीक नहीं है। अगर आप पड़ोसी राज्यों की बात करें, तो हरियाणा में 25-25 किलोमीटर दूर तक स्कूल और colleges नहीं हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले दो साल के अंदर 25 हज़ार सरकारी स्कूल बंद किए हैं और 40 प्रतिशत बच्चे आज भी कुपोषण से ग्रस्त हैं। क्या इस हिंदुस्तान को देखने के लिए इन शहीदों ने शहादतें दी थीं? क्या इस हिंदुस्तान को देखने के लिए भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था कि हम हिंदुस्तान के लोगों को बराबरी का यह दर्जा देंगे?

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA):** Mr. Gupta, because of the time constraint, hon. Chairman has instructed to restrict the time. Kindly take two more minutes.

**डा. सुशील गुप्ता :** उपसभाध्यक्ष जी, मैं पहली बार बोल रहा हूं, मैंने निवेदन किया है, मेरी मेडन स्पीच है। मैं पहली बार बोल रहा हूं। देश की कानून व्यवस्था को बनाने के लिए एक ऐसा स्तर होना चाहिए, जहाँ सब ठीक चले। दिल्ली की व्यवस्था को देखिए, यहाँ चुने हुए लोगों के हाथ में सत्ता न देकर माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय के हिसाब से दिल्ली पुलिस चलाई जा रही है। दिल्ली के अंदर अपराध बढ़ते हैं, दिल्ली के अंदर सरेआम कत्ल हो जाता है और दिल्ली पुलिस नागँवारा। अगर लेफ्टिनेंट महोदय के पास न विधायकों से, न मुख्य मंत्री से मिलने का समय होता है। अगर दिल्ली की कानून व्यवस्था को चलाना है, तो चुनी हुई सरकार को अधिकार मिलने चाहिए। अगर चुनी हुई सरकार इसको चलाएगी तो बेहतर रहेगा। मैं माननीय श्री अरविंद केजरीवाल को फिर भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि वे हर घर के अंदर जाकर बहुत कोशिश करते हैं। इस तरीके से नहीं - जिस प्रकार दिल्ली के तीन तरफ हरियाणा लगा है - आपने थोड़े दिन पहले की कानून व्यवस्था देखी, आपने रामपाल जी का केस देखा, राम रहीम जी का केस देखा, एक आंदोलन देखा। इस आंदोलन के तहत लोगों की संपत्तियाँ जलीं। कोई आदमी बोलने के लिए तैयार नहीं था, सरकार अपना राज धर्म निभाने में इसको भूल गई, सरकार कानून व्यवस्था को एक उचित दायरे के अंदर लाना भूल गई। अभी मैंने पिछले दिनों अखबारों में पढ़ा कि हरियाणा के अंदर 13 जिलों के अंदर लगातार रेप

cases हुए। महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और मुख्य मंत्री महोदय उस पर कुछ बोलने में लाचार थे। यदि आज मध्य प्रदेश की बात करें तो नेशनल क्राइम रिपोर्ट के हिसाब से मध्य प्रदेश के अंदर 13 रेप cases प्रतिदिन होते हैं, जो हिंदुस्तान का सबसे भयंकर गंदा रिकॉर्ड है, जो कि अनुचित रिकॉर्ड भी है। मैं इस सदन के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि सरकार को कहीं न कहीं इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि देश की कानून व्यवस्था मजबूत बने, देश के लोगों को बेहतरीन तरीके से सुरक्षा व्यवस्था मिले। मैं कहना चाहता हूं कि पिछले चार वर्षों से यह growth-oriented Budget नहीं है। हमेशा deficit के अंदर Budget जाता है।

महोदय, इस देश के अंदर नोटबंदी, फिर जीएसटी और अब दिल्ली के अंदर सीलिंग। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार की इन व्यापारियों से क्या दुश्मनी है? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग कहते हैं कि हमारे इधर मंदा है, व्यापार है, नौकरी नहीं है, बेरोजगार है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार और अखबार कहते हैं कि हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है। हिंदुस्तान तो तरक्की कर ही रहा है, लेकिन देश का 73 प्रतिशत पैसा, इन सब लोगों की जेब से निकलकर 1 प्रतिशत से कम लोगों के पास चला गया है, चंद घरानों के पास चला गया। क्या हम हिंदुस्तान को यह सामाजिक और आर्थिक समानता देना चाहते हैं?

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA):** Thank you very much, Guptaji.

**डा. सुशील गुप्ता :** मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को अपना सारा धन समेटकर अरबपतियों को देने की बजाय...जिस दिन आपने बजट पेश किया, उस दिन देश का जो इंडेक्स था, देश का जो शेयर बाजार था, उसमें लोगों के अरबों रुपये, करोड़ों रुपये तबाह हो गए, क्योंकि देश के मध्यमवर्गीय लोगों ने जिंदगी भर पैसा कमाकर अपनी कैपिटल शेयर बाजार में लगाई थी। आपने एक राहत कही कि हम इसके ऊपर लॉंग टर्म कैपिटल गेन्स लगाएंगे और शेयर बाजार धड़ाधड़ गिरता चला गया। आपने इस सदन के अंदर कहा कि हम एक्साइज़ ड्यूटी घटाकर, देश के अंदर न्यूनतम पेट्रोल की कीमत घटाएंगे, लेकिन उसी दिन, उसी रात में बाजार के अंदर पेट्रोल महंगा हो गया, आपने उसका बाजार भाव बढ़ा दिया। हम देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री महोदय यहाँ पर बैठे हैं, आप एक ऐसी योजना लेकर आएं, जिससे देश का व्यापारी शिक्षा के माध्यम से, चिकित्सा के माध्यम से, एक अतिरिक्त टैक्स के माध्यम से अपने आपको इस देश के अंदर सुरक्षित महसूस करे।

(3A/KLG पर जारी)

KLG-GSP/3A/6.10

**डा. सुशील गुप्ता (क्रमागत):** उसका व्यापार बढ़े और दिल्ली में सीलिंग से मुक्ति मिले। व्यापारियों के साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि हमारे जो नौकरी पेशा हैं, हमारे जो सर्विस क्लास के लोग हैं, उनके लिए आपने 2014-15 से टैक्स फ्री इनकम ढाई लाख रुपए रखी है। जब आप विपक्ष में रहकर प्रतिपक्ष के नेता थे, इसी सदन में आपने

कहा था कि टैक्स फ्री इनकम पांच लाख रुपए होनी चाहिए और आपने यही बात अपने अमृतसर के चुनाव के दौरान भी कही थी। महोदय, मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस देश के सर्विस क्लास लोगों के लिए आप इस टैक्स फ्री इनकम की सीमा को बढ़ाइए।

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA):** One moment, please. I do not want to interrupt your maiden speech but considering the situation and time constraint, please take one more minute and conclude.

**डा. सुशील गुप्ता :** ठीक है, महोदय। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आपने 40,000/-रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन तो दी, लेकिन उसके विपरीत आपने घुमाकर उसे वापस भी ले लिया, क्योंकि आपने मेडिकल, ट्रांसपोर्ट चार्जेज की डिडक्शन की छूट वापस ले ली और साथ ही 4 परसेंट का सेस भी लगा दिया। मैं चाहता हूँ कि इस 40,000/-रुपए की छूट को बढ़ा कर 75,000/- रुपए करें। माननीय महोदय के माध्यम से मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस ढाई लाख रुपए की टैक्स फ्री इनकम को आप पांच लाख रुपए करें, ताकि देश के नौकरी पेशा लोग अपनी मेहनत की कमाई से यह फील कर सकें कि हम इस देश के अंदर आराम से रह रहे हैं।

महोदय, मैं रोजगार की बात करना चाहता हूँ। हमें नए रोजगार के लिए साधन खोजने चाहिए। बजट के अंदर ऐसा प्रोविजन होना चाहिए कि देश का पढ़ा-लिखा नौजवान, युवा बेहतरीन नौकरी पा सके। आज जो यहां पर जुमला बना - पकौड़ा रोजगार योजना या और कोई योजना, मैं उनकी बात नहीं करना चाहता, मैं सीधे-सीधे

सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप ऐसे संसाधन उत्पन्न करें, जिनसे देश के लोगों को रोजगार मिले। रोजगार न मिलने से युवक गुनाह के रास्ते पर चल पड़ते हैं और जब युवक गुनाह के रास्ते पर चलेंगे, तो उसका खामियाज़ा आज के पूरे हिंदुस्तान को ही नहीं, आने वाली जेनरेशंस को भी भुगतना पड़ेगा और फिर उनको उस रास्ते से वापस लाना मुश्किल होगा। अंत में, मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस देश के किसान को यूरिया, खाद्यान्न के समर्थन मूल्य की बात करते हैं , बीमा फसल की बात करते हैं, लेकिन यथार्थ में कुछ नहीं मिलता। आप उसको यथार्थ में लाइए, ताकि देश का किसान, जो हमारा अन्नदाता है, उसको हौसला मिले।

महोदय, मैं एक मिनट और लूंगा। मैं कहना चाहता हूँ कि चुनाव के दौरान यह कहा गया था कि पाकिस्तान अगर हिंदुस्तान के जवान का एक सिर काटेगा, तो उसके बदले में हम दस सिर काट कर लाएंगे। आज उसके विपरीत माहौल दिख रहा है। देश की सेना का मनोबल ऊंचा करने के लिए अगर कोई जवान शहीद होता है, तो उसके परिवार को एक करोड़ रुपए मिलने चाहिए और बजट में यह प्रोविजन भी होना चाहिए कि उसके बच्चे को भी नौकरी मिलेगी, ताकि देश के जवान सीना चौड़ा करके अपनी ड्यूटी निभाएं।

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA):** Kindly understand the situation and conclude in one minute. Please wind up.

**डा. सुशील गुप्ताः** महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के विकास की बात होती है और आए दिन धमकी दी जाती है, कभी दिल्ली का पानी पड़ोसी राज्य रोक

देता है, दिल्ली के डीडीए में एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई, जो बीस साल का मास्टर प्लान अंतिम साल में पूरा करती है और अंतिम साल के अंदर कहते हैं कि यह समय पूरा हो गया, नया मास्टर प्लान बनेगा।

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA):** You are speaking well but there is no time. I have to call the next speaker.

**डा. सुशील गुप्ता:** महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के अदंर लाखों लोग मलिन बस्तियों के अंदर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। देश की राजधानी का चेहरा हम क्या बनाना चाहते हैं? उनको पक्के मकान बना कर देने होंगे। ...

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA):** Shrimati Viplove Thakur.

**डा. सुशील गुप्ता:** यह काम भारत सरकार करे।

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA):** It is enough.

**डा. सुशील गुप्ता:** महोदय, मैं अंतिम बात कहना चाहता हूँ कि उनको आप चार मंजिले पक्के मकान बना कर दें। इससे आपको 75 परसेंट जमीन खाली मिलेगी। उसके बाद उनकी शिक्षा के, चिकित्सा के लिए काम हों।

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA):** You have conveyed enough. Thank you, Mr. Gupta. Please conclude.

**डा. सुशील गुप्ता:** महोदय, मैं आपका आभारी हूँ, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरे पास दिल्ली के विषय में, देश के विषय में बोलने के लिए काफी था, मैं माननीय वित्त

मंत्री जी विनती करूंगा कि इन विषयों पर गौर करें, ताकि देश का भला हो सके, धन्यवाद।

(समाप्त)

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA):** Thank you. Now, Shrimati Viplove Thakur.

**श्रीमती विप्लव ठाकुर (हिमाचल प्रदेश)** : उपसभाध्यक्ष जी, जब देश का बजट आने वाला होता है, तो लोगों में बहुत उत्सुकता होती है। लोग बड़े ध्यान से और दिल लगा कर टीवी के सामने इसलिए बैठे होते हैं कि पता नहीं, हमें क्या मिलने वाला है, हमारी क्या भलाई होने वाली है, हमें क्या फायदा होने वाला है, हमें क्या उन्नति मिलने वाली है।

( 3बी/एकेजी पर जारी)

AKG-SK/3B/6.15

**श्रीमती विप्लव ठाकुर (क्रमागत)** : यह जो बजट है, यह हर मोर्चे पर विफल रहा है, कोई भी वर्ग इससे खुश नहीं है। न तो किसान खुश हैं, जिनके लिए इन्होंने इतना बड़ा कहा है - farmers, farmers, farmers. आज farmers भी खुश नहीं हैं, महिलाएँ भी खुश नहीं हैं, बच्चे भी खुश नहीं हैं, व्यापारी भी खुश नहीं हैं, कोई भी वर्ग इस बजट से खुश नहीं है, क्योंकि इस बजट में है ही कुछ नहीं।

मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन मैं वित्त मंत्री जी से एक बात जानना चाहती हूँ कि इन्होंने किसान की परिभाषा क्या रखी है? क्या किसान सिर्फ वही है, जो गेहूँ, ज्वार, मक्की, धान बोता है या किसान वह भी है, जो हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में रहता है, जो वहाँ पर सेब की फसल करता है, fruit की फसल करता है, उसे उगाता है? उसको जो नुकसान होता है, क्या उसकी भरपाई के लिए भी इन्होंने कुछ रखा है? कुछ नहीं रखा है। जितने hill areas हैं, उनके लिए स्पेशल बजट चाहिए, चाहे वह नॉर्थ-ईस्ट है, चाहे हिमाचल प्रदेश है, चाहे जम्मू-कश्मीर है, चाहे उत्तराखंड है, क्योंकि अगर यहाँ पर एक सड़क बनानी है, तो अगर मैदानों में इसके लिए एक करोड़ लगता है, तो पहाड़ों में इसके लिए 5 करोड़ लगता है। लेकिन इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। आज हिमाचल प्रदेश का जो सेब है, fruits हैं, सब्जियाँ हैं और जो वहाँ off season सब्जियाँ उगाई जाती हैं, उनके लिए भी किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। इस बजट से कोई खुश नहीं है।

महिलाओं की तो बात ही क्या करनी है ! ये बहुत महिला-महिला करते हैं, उसके सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन इन्होंने उसका बजट भी कम कर दिया है। महिला के हेड में 2,700 करोड़ से 2,400 करोड़ कर दिया गया है। कुपोषण के लिए जो बात होती है, तो 1.2 करोड़ बच्चे हैं, जिनके लिए 8 हजार करोड़ चाहिए, अगर हम उनको सेहत देना चाहते हैं। इसके लिए भी कहीं प्रावधान नहीं है।

बड़ी बातें की जाती हैं। अभी गुप्ता जी ने कहा, मैं भी पिछले पेपर्स देख रही थी, जब पाकिस्तान से कहा जाता था कि एक सिर आएगा, तो हम 10 सिर देंगे। आज यहाँ

मेरी बहन स्मृति इरानी जी नहीं बैठी हुई हैं, इन्होंने कहा था कि चूड़ियाँ भेजी जाएँगी। स्मृति जी, अब तो आप इस कैबिनेट में हैं, भेजने की जरूरत भी नहीं है, इनको चूड़ियाँ पहना ही दीजिए, जो अभी इस तरह से काम कर रहे हैं। कहाँ हैं वे? मैं बात नहीं करना चाहती हूँ। आज रोज हमारे यहाँ किसी न किसी शहर में हमारे फौजी के शव आते हैं, ताबूत में डले हुए आते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ बोल नहीं सकते।

जम्मू-कश्मीर के हालात देखिए। अभी मेरे भाई जम्मू-कश्मीर के लिए बोल रहे थे कि क्या हुआ, क्या किया, लेकिन मेरे भाई, 2000 से लेकर 2009 तक इतनी बुरी हालत नहीं थी, जो आज हो रही है। कहाँ हैं वे? कहाँ हैं वे बातें? क्या वे केवल जुमले ही थे? आज इतना कुछ दिया गया है, ये सिर्फ बातें हैं, बातों के अलावा कुछ नहीं है।

हमारी कौन सी विदेश नीति है? हमारा कौन सा neighbour है, पड़ोसी देश है, जो हमसे खुश है? नेपाल था, हमने उसको भी गँवा दिया। श्रीलंका हमसे नाराज है, म्यांमार हमारे साथ नहीं है, बंगलादेश को देख लीजिए, चीन हमें डरा रहा है, पाकिस्तान रोज हमसे कहता है और हम विदेश घूम रहे हैं। खूब विदेश जा रहे हैं। कौन सी FDI आ गई है विदेश से, मुझे बताएँ? जितना खर्च विदेशों में जाने में हुआ है, उसी से हम अपने देश का और भी भला कर सकते थे, उसको और भी उन्नत कर सकते थे। हमारी कोई नीति नहीं है।

मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। नड्डा जी यहाँ बैठे हैं, एक मिनट, हमारे यहाँ जो मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, चाहे वह नाहन में है, चाहे हमीरपुर में है, चाहे मंडी में, जब MCI की टीम आती है, तो कहाँ से faculty के प्रोफेसर्स लाए जाते हैं?

कभी इंदिरा मेडिकल कॉलेज से जाते हैं, कभी टांडा से जाते हैं। नड्डा जी, हमें ऐसे मेडिकल कॉलेज नहीं चाहिए, जहाँ पर faculty के लिए प्रोफेसर्स ही न हों। आप कौन से बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, जहाँ सुविधाएँ ही नहीं हैं?

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA):** Thank you, Viplove*ji*.

**श्रीमती विप्लव ठाकुर :** नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बोल रही हूँ और हमेशा मेरे साथ ऐसा किया जाता है। मैं दो मिनट में अपनी बात खत्म करती हूँ।

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA):** One more minute, please.

**श्रीमती विप्लव ठाकुर :** हर प्रदेश में insurance की सुविधा है। एक साल के लिए 5 लाख तक के लिए कहा गया है।

मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि इन्होंने कहा कि अगर बैंक में minimum पैसा नहीं होगा, बड़े-बड़े शहरों में यह सीमा 3 हजार है, कहीं एक हजार है, तो उसके ऊपर penalty लगेगी। वित्त मंत्री जी, penalty के ऊपर भी GST लगा दिया गया है। अगर penalty भी लेनी है, तो एक गरीब का क्या कसूर है कि वह बैंक में एक हजार रुपए भी नहीं रख सकता और उसकी penalty के ऊपर भी आपका GST है।

(3सी/एससीएच पर जारी)

SCH-YSR/6.20/3C

**श्रीमती विप्लव ठाकुर (क्रमागत) :** महोदय, प्रधान मंत्री आवास योजना की बातें हो रही है। जो फ्लैट लेगा, उस पर भी वह जीएसटी देगा।

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA):** Thakur ji, please conclude.

**श्रीमती विप्लव ठाकुर :** आप मुझे बताइए कि यह कहां का न्याय है? इस तरह से सरकारें नहीं चलती हैं। आप तैयार हो जाइए, क्योंकि अगर हमने गलतियां की थीं, तो हमने भुगत लीं, अब आप भी भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। वैसे भी आपका यह बजट चार महीने का है।

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA):** Thank you.

**श्रीमती विप्लव ठाकुर :** आप इस फसल का इंतजार कर रहे हैं कि यह फसल आए और हम किसानों को पैसा दें, फिर अगली फसल के लिए कुछ नहीं हो।

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA):** Thank you.

**श्रीमती विप्लव ठाकुर :** आप इलेक्शन जीत जाएं, यह होने वाला नहीं हैं। आप इस भुलावे में मत रहिएगा, क्योंकि आपको जाना ही होगा और आप जाएंगे। जनता आपसे नाराज़ है।

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA):** Thank you, Mrs. Thakur. Please.

**श्रीमती विप्लव ठाकुर :** आपने राजस्थान में देख लिया, गुजरात में देख लिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

(समाप्त)

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA):** Thank you very much, Mrs. Thakur. Now Mr. Ashok Siddharth. Strictly you have three minutes.

**श्री अशोक सिद्धार्थ (उत्तर प्रदेश) :** सर, मुझे पांच मिनट दीजिए। दलितों के साथ ही यह अन्याय क्यों हो रहा है?

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आपने मुझे केन्द्रीय बजट पर बोलने का मौका प्रदान किया, इसके लिए धन्यवाद। श्रीमन्, जैसे ही बजट सत्र आता है, वैसे ही देश के आम नागरिकों में चर्चा होने लगती है कि आने वाले बजट में उनके लिए क्या होगा? इसका कारण भारत में वित्त मंत्री के द्वारा पढ़ा जाने वाला बजट भाषण है, जो देश के नाम एक संदेश होता है। इस संदेश से जनता को यह भी पता चलता है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में आम जनता के प्रति सरकार की सोच क्या है?

महोदय, जहां तक वर्ष 2018-19 के बजट की बात है, भले ही सरकार की चाटुकारिता करने वाले आर्थिक विशेषज्ञ इस असंतुलित बजट को संतुलित बता रहे हों, लेकिन वास्तव में यह बजट गरीबों, मज़दूरों, छात्रों, नौजवानों, बेरोज़गारों के हित में नहीं है और खासकर दलितों और आदिवासियों के लिए इस बजट में कोई खास प्रावधान करने का काम नहीं किया गया है। किसानों से लेकर महिलाओं की स्थिति भी वैसी ही है। इस सदन के वरिष्ठ सदस्यों ने सरकार को चेताने का काम किया है, इसलिए मैं उन बातों को दोबारा दोहरा कर सदन का समय बरबाद नहीं करना चाहता हूं। इस बजट में अपने अल्प समय में ही मैं अपनी बात रखूंगा। चूंकि मैं दलित समाज से ताल्लुक रखता हूं और एक साधारण से दलित परिवार में पैदा हुआ हूं, फिर भी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा, आदरणीया बहन जी की वजह से मुझे देश के इस सर्वोच्च सदन में आने का मौका मिला है। इस बजट में दलितों और आदिवासियों के

उत्थान की बात कहीं भी दिखाई नहीं देती है, इसलिए इसके संबंध में मैं सरकार से कुछ बातें जानना चाहता हूं। जब सरकार ने 2014-15 में अपना पहला आम बजट पेश किया था, तो बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने उस बजट में दलितों के लिए, SCs/STs के लिए 2.8% का प्रावधान रखा था, जो चार साल गुज़रने के बाद, आपके इस आखिरी बजट में घट करके 2.32% रह गया। क्या चार साल में दलितों की तरक्की हो गई या फिर उनकी आबादी कम हो गई? बजट प्रस्तुत होने के बाद से लेकर अब तक यह प्रश्न हमारे दिमाग में है, जो अभी तक अनुत्तरित है कि सरकार ने इस संबंध में क्या किया है?

मान्यवर, भोजन, पानी और ऑक्सीजन की तरह मानव जीवन के लिए गरिमा और सम्मान भी जरूरी होता है, लेकिन अगर हम इस बजट के पूरे प्रावधानों को देखें, तो कहीं भी दलितों के लिए सम्मान से जीने लायक व्यवस्था करने का काम नहीं किया गया है।...(समय की घंटी)... सिर्फ दो बातें कह कर मैं अपनी बात को समाप्त कर दूंगा, क्योंकि आपने स्ट्रिक्ट्ली तीन मिनट के समय के लिए कहा है। चूंकि मैं एक अनुशासित पार्टी का अनुशासित सिपाही हूं, इसलिए सिर्फ आधे मिनट में मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA):** Three minutes are over.

**श्री अशोक सिद्धार्थ :** माननीय वित्त मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं। मैं वित्त मंत्री जी से कम से कम यह अवश्य चाहूंगा कि दलितों और आदिवासियों के लिए जो फंड का आवंटन

हो, उसके लिए ऐसी नीति बनाई जाए, ताकि आज जो प्लान या नॉन-प्लान के विलय में झूल रही है, उसे वहां से हटा करके आवश्यक कानूनी रूप दिया जा सके।

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA):** That is fine.

**श्री अशोक सिद्धार्थ :** मान्यवर, एक मिनट और दीजिए। प्लान और नॉन-प्लान के चक्कर में दलितों और आदिवासियों के लिए जो बजट दिया जाता है, वह एक तरह से सरकार की दया पर निर्भर है।

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA):** You have made your point. Thank you.

**श्री अशोक सिद्धार्थ :** वह सरकार की दया पर निर्भर न हो करके दलितों और आदिवासियों के लिए इस बजट में उचित व्यवस्था प्रदान करने का काम किया जाए।

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA):** Thank you Mr. Siddharth. You have conveyed your point.

**श्री अशोक सिद्धार्थ :** सरकार में दलित समाज के लोग भी मंत्री हैं और वित्त मंत्री जी भी बैठे हैं।

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA):** You have made your point. Thank you.

**श्री अशोक सिद्धार्थ :** वे सोचें कि आज दलित समाज के साथ जो हो रहा है, तो उनमें जो लोग बैठे हैं, उनके साथ और पूरे दलित समाज के साथ यह सरकार क्या करने जा रही है? इसके लिए उनको अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए।

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA):** Brevity is the soul of wit, Mr. Siddharth.

**श्री अशोक सिद्धार्थ :** मान्यवर, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

(समाप्त)

-YSR/VKK-RPM/3D/6.25

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA):** Now, Shri Ananda Bhaskar Rapolu. You have four minutes.

**SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU (TELANGANA):** Respected Vice-Chairman, Sir, being the son of the weaving community, I express my anguish for reducing the Budgetary support to the handloom weaving sector from Rs.600 plus crore to Rs.300 crore. Being the son of the Other Backward Classes, I express my anguish about your insensitivity to our demand to have the OBC Sub-Plan. As you have done away with Plan and non-Plan Budgetary approaches, you have safely shelved the Scheduled Castes Sub-Plan and the Scheduled Tribes Sub-Plan. Hence, the demand for Other Backward Classes Sub-Plan is not being taken up seriously. This is the grave concern of more than 50 per cent of the population of India which needs to be addressed by the Union Government immediately. Being the son of Telangana, I would like to flag before you that Telangana is being

deprived of the provisions that are supposed to be provided through the enactment and you are also not showing necessary concern towards the provision of schemes and programmes and providing institutes to the Telangana State. At this juncture, my brothers and sisters of Andhra Pradesh are in agitation. Yesterday, they observed total *bandh* throughout the residuary State of Andhra Pradesh. My colleagues in both the Houses are standing in the Well and agitating and expressing their anguish. Even earlier, I had pleaded with you to have two types of special status programmes for the States — one for the very sensitive hilly areas and another for such States which have real fiscal complications to cater to their necessities.

**(THE VICE-CHAIRMAN, DR. SATYANARAYAN JATIYA, in the Chair)**

Sir, Andhra Pradesh is one such State which needs to be addressed by you with a special provision of funding and you have to assuage them by giving a new type of special status to Andhra Pradesh State. Then only, the anguish and agitation will subside. Otherwise, it will take the shape of a movement which will become a bigger problem in times to come. आपके शासन काल का अब सिर्फ एक साल बाकी है और चार साल गुजर गए हैं। "कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे" इन चारों सालों की आपकी सत्ता देखने के बाद लोग यह

भी सोच सकते हैं कि अगर वर्ष 2014 में वर्तमान प्रधान मंत्री के बदले, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी यदि प्रधान मंत्री बन गए होते, तो बहुत अच्छा होता। यह सोच अभी भी लोगों के दिलों में है, लेकिन बाहर निकलने का साहस नहीं हो रहा है। आपको यह बात समझनी चाहिए। अगर श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, प्रधान मंत्री बन कर इस देश की सत्ता को चलाते, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के असली राजधर्म का पालन होता। उसके साथ ही साथ मैं आर्य समाज पद्धति के, ब्रह्मऋषि दयानंद सरस्वती से लेकर पं. दीन दयाल उपाध्याय तक की जो-जो विचारधाराएं हैं, उन्हें मैंने पूरा पढ़ा है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप पं. दीन दयाल उपाध्याय के बताए मार्ग पर भी चलने को तैयार नहीं हैं। आपका असली चेहरा अब सामने आ रहा है। इसलिए पूरे देश की जनता आपसे व्यथित है। वह आपके सामने है। You know that. You understand the gravity of the turmoil that is brewing all across the country. Your GDP is not being believed. Your arithmetic is not being believed. And you have the phobia for Pandit Jawaharlal Nehru. Thanks to your memory, *ninda* is also a great *stuti* before the spiritual authority. If you respectfully blame somebody in the form of *ninda stuti*, it will also become a prayer. You are obsessed with Pandit Jawaharlal Nehru. He brought in the mixed economy. He ensured what is there today before you and what you are administering now.

(Contd. by BHS/3E)

-VKK/BHS-PSV/3E/6.30

**SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU (CONTD.):** Have you ever bothered to look at the necessities of the Indian population? Your GDP cannot cater and it is an established fact by the well-known international economist that GDP calculation is not going to give you the necessary assessment and it will not indicate the progress and development, that is, having what you have mentioned as ease of living. It is not even ease of doing business and it is not even ease of living. In such conditions, what is supposed to be done? Recently, under the parameters of the Inclusive Development Index, seventy-four countries' emerging economies have been considered. In those seventy-four emerging economies, where is India standing?

**उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया):** आनंद भास्कर जी, आपका समय समाप्त हो गया है।

**SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU:** Please look at it. India is standing at number 62 in the ranking as we are not inclusive economically, as we are not inclusive socially and we are not at all inclusive administratively.

**THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA):** Please conclude. ...(Interruptions)... Ananda*ji*, your allotted time is over. ...(Interruptions)...

**SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU:** This has become a bigger complication as the doubts are looming large about the calculations of the

GDP. I urge upon the Union Finance Minister to look into the possibility of inclusion and assessment of the model under way in the Inclusive Development Index which will show what exact inclusive nature we could attain with our people.

**THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA):** Thank you. ...(Interruptions)...

**SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU:** Besides that, I would like to urge upon the Union Government to have federalism in a proper form. You have mentioned about the cooperative federalism but there is nothing in practice before you as the federalism. You are not taking the State Governments on board while considering the requirements and the expectations of the State.

**THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA):** Please conclude. ...(Interruptions)... Now, Shri Ripun Bora. ...(Interruptions)...

**SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU:** Take the case of Telangana as well. This is reflecting your attitude towards the treatment towards a State. Economic federalism is required, cultural federalism is required, social federalism is required and then only the fusion of the political federalism is possible for which your Budget has now reflected which you could not convey.

**उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया):** आनंद भास्कर जी, अब आप कन्क्लूड करिए। Shri Ripun Bora. ...(Interruptions)...

**SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU:** This has taken away the great opportunity before you as only one year is before you. I plead, I suggest, सह नाववतु, सह नौ भुनक्तु...। ऊँ शान्ति, शान्ति, शान्ति। जय हिन्द।

(समाप्त)

**THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA):** Thank you. Shri Ripun Bora.

**SHRI RIPUN BORA (ASSAM):** Thank you, Sir. You have given me the opportunity at the end.

**THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA):** Five minutes only. ...(Interruptions)... Please conclude in five minutes. ...(Interruptions)...

**SHRI RIPUN BORA:** Sir, my humble submission to you is that I am the last speaker of my party and I am the only speaker from the North-Eastern Region, the vast and neglected region. Kindly do not interrupt me. I will speak very briefly and I will not take much time. ...(Interruptions)... महोदय, मैं अपनी बात की शुरुआत हमारे वित्त मंत्री के एक quotation से करता हूँ। उन्होंने जब air connectivity के ऊपर बजट दाखिल किया था, तो एयर पोर्ट बढ़ाने के लिए बोला

था। उसमें उन्होंने बोला था कि हम लोग इस बजट में हवाई चप्पल पहनने वालों के लिए हवाई जहाज उपलब्ध करायेंगे। सर, सिर्फ एयरपोर्ट बढ़ा देने से हवाई चप्पल पहनने वालों के लिए हवाई जहाज उपलब्ध नहीं होगा, जब तक उनके fares कम नहीं होंगे। सर, हवाई चप्पल कौन पहनता है? जो poorest of the poor है, वह इसे पहनता है। वे लोग तीन-चार महीने पहले कभी टिकट बुक नहीं करते हैं। तीन-चार महीने पहले टिकट बुक करने से उनको 3,000 या 4,000 में दिल्ली तक का टिकट मिलता है, लेकिन उन लोगों की मजबूरी है कि उन्हें बीमारी के इलाज के लिए चेन्नई जाने के लिए, मुम्बई जाने के लिए और दिल्ली आने के लिए 24 hours-48 hours के अन्दर टिकट बुक करना होता है। हमारे गुवाहाटी से तो 48 hours में टिकट बुक करने से टिकट का दाम कम से कम 10,000 से 25,000 तक होता है। अभी हकीकत यही है कि यह जो हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी है, उसकी एक साल की कमाई लगभग 20,000 रुपये होती है। इसके बावजूद भी हवाई जहाज में यह जो package है, baggage है, उसमें extra baggage के लिए, 1 Kg के extra baggage के लिए extra 300 रुपये देने पड़ते हैं। इसलिए यह कोई दूसरा कुछ नहीं है, बल्कि यह भी एक सपना है। जैसे मोदी जी का 15 लाख रुपये का सपना था, वैसे ही यह भी हमारे गरीब लोगों के लिए एक स्वप्न के अलावा कुछ नहीं है।

(3एफ/एनकेआर पर जारी)

**SHRI RIPUN BORA (CONTD.):** Sir, my second point is, the hon. Finance Minister in the Budget...

**THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA):** You please conclude. आप नियत समय में, दो मिनट आपके पास हैं, उसमें अपनी बात पूरी करिए। ..(व्यवधान)..

**SHRI RIPUN BORA:** No, Sir, you have given everybody more time. ...(Interruptions)...

**उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया) :** आपकी पार्टी के 25 मिनट ज्यादा हो गए हैं। अब खत्म करिए। ..(व्यवधान)..

**SHRI RIPUN BORA:** Sir, my second point is that in the Budget, the Finance Minister has very loudly and very proudly said that this is a Budget for the poor and this is a road map for the poor people; this is a road map for the farmers, he said these things. Now, Sir, my questions are: what steps has the Budget taken for increasing the purchasing power of the people? What steps has the Budget taken to control the sky-rocketing prices of all commodities. What steps has the Budget taken to fulfill the promises of the BJP Government to make the prices half if they come to power as what was at the time of the UPA Government. Sir, as a student of economics, I know that higher the circulation of money in the market, the higher the purchasing

power of the people. Now, what has the Government done for increasing the purchasing power? They have cut the circulation of money by demonetization; by cashless economy; by digital economy, by imposing restrictions on bank withdrawals and by imposing service taxes in case of withdrawals from the ATMs. So, now, how will this purchasing power increase? On the one hand, we are curtailing the purchasing power and on the other hand, we have these sky rocketing prices. So far as the price rise is concerned, I do not want to talk about the other prices but I will only mention about the petrol prices.

**THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA):** Please conclude.

**SHRI RIPUN BORA:** Sir, just two minutes. ...(Interruptions)...

**THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA):** No; only one sentence, the final sentence. ...(Interruptions)...

**SHRI RIPUN BORA:** Sir, you have given everybody five minutes. In 2004, in the international market, when the crude oil price per barrel was 30$, at that time, the petrol price was Rs. 33 to Rs. 38 and the diesel price was Rs. 21 to Rs. 27 and in 2016, when the crude oil price per barrel was 30.53$, the petrol price had gone from Rs. 59 to Rs. 66 per litre and the diesel price had gone from Rs. 44 to Rs. 52 per litre. And, now, the most unfortunate part is

that, in this current year, the crude oil price has come down to the level of 2004 but in spite of that the petrol price is here approximately Rs. 73 to Rs. 75 per litre and the diesel price is Rs. 64 to Rs. 65 per litre. Now, Sir, from April 2014 to March 2016, prices of crude oil in the international market have fallen by 64 per cent and during this period the excise duty on petrol went up by 126 per cent. Sir, this BJP led NDA Government during their three-and-a-half years of tenure raised the excise duty by nine times and as a result, we the common people are suffering because of the sky rocketing prices. Now, Sir, the hon. Finance Minister is here; Shri Ravi Shankar Prasad is here but Shrimati Sushma Swaraj is not here and the Home Minister is not here. I want to show when during our UPA Government, there was high price, what they have done...

**THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA):** All the Ministers are here. ...(Interruptions)... Please don't show it. ...(Interruptions)... Please don't show it. ...(Interruptions)... Please conclude. ...(Interruptions)...

**SHRI RIPUN BORA:** No, no, Sir, Shri Arun Jaitley is here. He had started agitation all over India by showing gas cylinder...

**THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA):** Now, I am calling the Finance Minister.

**SHRI RIPUN BORA:** And, Sushma Swaraj*ji* by taking up garland of onion....

**THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA):** No, not allowed. Nothing will go on record.

**SHRI RIPUN BORA: ***

(Followed by DC/3G)

---

***Not Recorded**

-RL/DC-DS/3G/6.40

**THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA):** Thank you. Nothing is going on record. ...(Interruptions)...

**SHRI RIPUN BORA: ***

**(MR. CHAIRMAN in the Chair)**

**MR. CHAIRMAN:** Please. ...(Interruptions)... Nothing is going on record. Why are you unnecessarily wasting your energy? ...(Interruptions)...

**SHRI RIPUN BORA: ***

**MR. CHAIRMAN:** Nothing shall go on record, both print and electronic. ...(Interruptions)... वित्त मंत्री जी, एक मिनट। One minute. ...(Interruptions)... Mr. Ramesh, Mr. Venkatesh, Mr. Mohan Rao and Madam, please go to your seats. Please hear my advice. Please go to your seats. Just hear what I am going to say. ...(Interruptions)... वित्त मंत्री जी, एक मिनट। Hon. Members, I have something to say to the House and then, the Finance Minister will reply to the Budget and he has some Resolution also to move.

I am saying this with a heavy heart. I hope everybody understands it.

---

***Not recorded.**

We are coming to the end of the first part of the 245th Session of the Rajya Sabha today and we shall be meeting again after about a month to continue our discussions on the Budget. I must confess that I am deeply pained at the way this Session has progressed. As the Chairman, it is my responsibility because at the end of the day, I am accountable to the people. They will see how the House is conducted, how discussions have gone on. What I am deeply disturbed with is the utter disregard for the parliamentary procedure and the unruly behavior so unbecoming of the high position we occupy in the society as parliamentarians.

Dear Members, the question I have been asking myself, and probably many Indians watching us on the television screens would be thinking of, is this: Can we ever make our Parliament an effective instrument of change through informed debates, constructive criticisms and orderly proceedings? I was hoping that we shall collectively strive to uphold and maintain the dignity, sanctity and supremacy of Parliament as we had pledged in 2012 to commemorate the 60th Anniversary of the sitting of the Parliament. I shall still keep hoping that we shall exercise the necessary restraint and behave with appropriate severity and dignity. I find it a sad commentary on the functioning, that we have lost nearly ten hours during this brief Session due to disruptions and forced adjournments. We could not have Question Hour on five days and there was also no Zero Hour on five days.

Dear Members, we certainly should not go in this manner any longer. I appeal to each one of you, please consider this as a sacred institution which should reflect the hopes and aspirations of 130 crore people. This is not aimed at any party--this party or that party. As far as the Chair is concerned, I am concerned about the House. It is an institution that decides the destiny and charts the direction of national development. That is why people have high hopes on us. We are so privileged to be in this House because of the people's trust on us. We must use the opportunity wisely by debating, discussing and evolving solutions to a vast number of public concerns. Let us not have slanging matches

between parties and stoop down to competing with each other on unparliamentary language or behavior. When we meet again in March, it is my fervent hope and an earnest appeal to each one of you that we shall turn a new leaf in our Parliament's history through orderly, informed and constructive debates.

Hon. Members, over the last few days, I have been telling the floor leaders of the quality of the debate on the Motion of Thanks to the President, whether from this side or that side, and I am very much impressed the way the debate was initially conducted and the contribution made positively from that side and also critically from this side in their own way. They have got every right and we have such good Parliamentarians here, who are articulate and have the capacity to argue and also to put forth their point of view. That being the case, when we have such talented material on all sides, why should we lose the opportunity to have the debate? That is my only concern. All other things about individual actions and all, that I am not going to make any comment. And whatever has happened, that has been clarified in the morning. So I am not even touching that. Then, some people have given notice. That notice has been taken note of. That has been already announced. There was some mention about Rajya Sabha telecast by Shri Derek O'Brien. That also has been inquired into and a report, as has been given, has been sent to hon. Member also. There was some power failure. So, hon.

Members, I only request every one of you, please keep the prestige and the decorum of this august House. We are supposed to be the Elders. So, keep that in mind and respond in such a manner so that the prestige of the House goes up. I feel that such an atmosphere, quality debates, will become a regular feature like we had in the recent past. This is the only thing.

I now ask the Finance Minister to reply to the debate, including the issues raised by the Members.

(Ends)

(Followed by KR/3H)

---

**Pp 200 onwards will be issued as supplement.**

KR/MCM/3H/6.45

## STATUTORY RESOLUTION RE: INCREASING RATE OF BASIC CUSTOMS DUTY (BCD) ON CHANA (CHICKPEAS)

**&**

## THE UNION BUDGET, 2018-19 (CONTD.)

**THE MINISTER OF FINANCE (SHRI ARUN JAITLEY):** Mr. Chairman, Sir, thank you very much for this opportunity. We had two days' detailed discussion on the Budget, and this discussion will spill over to the second

part because there will be a detailed discussion on the Demands for Grants. ..(Interruptions)..

**SHRI C.M. RAMESH:** What about special assistance for Andhra Pradesh?

**MR. CHAIRMAN:** That also will be covered.

**SHRI ARUN JAITLEY:** Several issues, like the one Mr. Derek O'Brien raised on the Railways, when the Demands for Grants of the Railways are dealt with, I think, to his greater satisfaction, will be dealt with by my colleague, Shri Piyush Goyal in that debate itself. I will, therefore, try and be very brief considering the fact that Members have gone through the two day debate, and this debate will continue in the Demands for Grants and the discussion on this Finance Bill itself.

I am very grateful to all the Members, led by Mr. P. Chidambaram who initiated the discussion. Obviously, since my friends from Andhra Pradesh have been very deeply concerned about the issues facing their State. If the hon. Members permit me, I will just make a brief statement with regard to Andhra Pradesh. Considering the fact that when the State was bifurcated into two, we were amongst the Members, who had strongly felt that as a result of the bifurcation some justice has to be done to the residuary Andhra State because it was going to lose a large part of its revenue. There were

several commitments which have been made in the Andhra Pradesh Reorganisation Act, in this House , and before the State Government. Some of these commitments have been implemented; and some work is in progress. Many institutions have been created in the State of Andhra Pradesh since earlier institutions went to the State of Telangana. Money for the creation of the Capital and, for the Backward Districts has been given. The agency of NABARD is funding the Polavaram project. It is a continuous process which we will continue, and work will not be allowed to be stopped at any stage itself.

There are certain pending issues, which is also work in progress. I will just read a brief paragraph to inform my friends because over the last few days also meetings have been held. The Central Government had agreed to give a special assistance to the Government of Andhra Pradesh for a period of five years. Earlier this assistance was to be given by the Externally-Aided Programme. However, in the month of January, the State Government suggested an alternative method, and on the alternative method discussions have reached a very advanced stage and a solution is likely to be finalized soon.

With regard to revenue deficit for the year 2014-15, ten months of that year, a sum of Rs.3,979.50 crores has already been given. A resolution with regard to the determination of the final amount payable has been discussed and currently discussions are going on to finalise the gap, the difference in the perception has narrowed down.

As far as other issues are concerned, Durgarajapatnam Port, Integrated Steel Plant in the Kadapa District, Petroleum Cracker Complex, separate Railway Zone at Vizag, Vizag-Chennai and Bengaluru Industrial Corridor, all the concerned Ministries have been asked to look into these matters and take an early decision with regard to each one of these areas itself.

(Continued by 3J/KS)

KS-SC/3J/6.50

**SHRI ARUN JAITLEY** (contd.): So, this is work in progress, and at a very advanced stage.

Sir, the debate was initiated by my friend, Mr. Chidambaram. For the period 2004-14, the UPA Government was in power and, out of this period, as he himself mentioned, for the initial years, particularly till 2010, there was a boom in the global economy. He, in fact, mentioned that the Chief

Economic Advisor had referred to their management of the economy as a 'boom period'; that is not so. There was a boom in the global economy itself because of which India was also benefiting. Oviously, whenever any Government is in power, it has its own perception of implementing what it thinks is in the larger national interest.

Let me start off by saying that the UPA Government had started two important programmes. One was MNREGA and the other was the Right to Food. Even when the Government changed in 2014, we, in the NDA, felt that in the larger interest of the national economy it is in our own interest to continue these programmes. So, for MNREGA, last year and this year, I had already provided an amount of Rs. 55,000 crores in the Budget itself. Let me say this -- and I am not making a critical comment; it is a factual analysis -- that even when Rs. 40,000 crores was the maximum that the UPA would sanction, it was never able to spend that money. कभी 28 हज़ार करोड़ खर्च होता था, कभी 32 हज़ार करोड़ खर्च होता था। हम जितना बजट में sanction करते हैं - पिछले साल 48 हज़ार करोड़ किया तो 55 हज़ार करोड़ हो गया। इस साल 55 हज़ार करोड़ किया ...

**SHRI ANAND SHARMA:** If you allow me, Sir, I want to say something. Of course, it is not a critical issue. The fact, which we cannot deny, Arunji, is

that last year the increase was forced by circumstances because, after demonetisation, a large number of people lost their jobs, their daily wages and they went back to their villages, and MNREGA saved them. This time also some...

**श्री अरुण जेटली** : आनन्द जी, मैं आपको थोड़ा डेटा दूंगा। आप जिस भ्रम में जीते हैं और जिस भ्रम में ये भाषण भी किए गए, factual data उसको समर्थन नहीं देता है। इस साल भी हमने 55 हज़ार करोड़ किया है। Right to Food यानी food subsidy इस साल 1 लाख 70 हज़ार करोड़ है। किसी भी सरकार में ये कार्यक्रम शुरू हुए हों, ग्रामीण सड़कों पर जो खर्च होता था, उससे कई गुणा ज्यादा है , 27 हज़ार करोड़ सालाना। आप किसी भी लोक सभा सांसद से पूछ लीजिए, उसके क्षेत्र में कितना खर्च हो रहा है। गांव को सड़क से जोड़ देना, गांव के भीतर घर मिल जाना, गांव के अंदर शौचालय बन जाना, स्वच्छ भारत और शौचालय का जो निर्माण हुआ है, पिछले तीन-चार वर्षों में वह जिस गति से देश में बढ़ा है, वह अपने आपमें एक नया इतिहास लिख रहा है। केवल हर गांव तक बिजली नहीं, वह तो आपके समय भी कोशिश हो रही थी कि बिजली पहुंचाई जाए, लेकिन आज हर गांव में हर घर को spot किया जा रहा है कि उस घर तक बिजली पहुंच जाए। Interest subvention - आप आंकड़ों की तुलना कर लीजिए, उसकी संख्या लगभग दोगुनी हुई है, crop insurance को उसके साथ और जोड़ा गया है। इसलिए गरीबी का उन्मूलन करने के लिए पूरे बजट में आपको कितनी entries मिल जाएंगी जो एक के बाद एक उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करती हैं।

(3के-पीआरबी पर जारी)

PRB-KGG/3K/6.55

**श्री अरुण जेटली (क्रमागत):** केवल इतना नहीं, एक आलोचना जो हम लोग आपकी सरकार के समय करते थे कि आपने right approach तो दे दी, लेकिन productivity बढ़ाने के लिए जो बाकी सुधार करने चाहिए थे, उनका क्या हुआ ? आप पिछले 2-3 साल का इतिहास देख लें। आधार के बारे में, मैं यह जानता हूं कि जब आपकी सरकार थी, तब भी सरकार में division था। There was a divided opinion in your Government. एक मंत्रालय चाहता था, एक विभाग PMO चाहता था, शायद कई लोग नहीं चाहते थे और इसीलिए आज तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि आप उसके पक्ष में हैं या उसके खिलाफ हैं। आप लोगों ने कोशिश की, लेकिन GST को आगे लाने में सफल नहीं हो पाए, हम लोग ले आए। इसमें आपका भी सहयोग रहा है। मैं बैंकों के साथ जो हुआ उसकी अलग से चर्चा करुंगा। लेकिन जो सबसे विचित्र टिप्पणी की गई कि बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे में यह लिख दिया गया कि employment के संबंध में, रोजगार और कृषि के संबंध में और शिक्षा के संबंध में अभी देश में बहुत कुछ होना है because the Chief Economic Advisor is realistic in writing that we have a lot of distance still to cover in these areas, the impression was created as though these are the three problem areas created in the last four years! On the cumulative effect of resources of historical backwardness, what is the impact of Congress rule in all these years? 55 साल आप सरकार में रहे, अगर

आपके नारे मंजूर कर लिए जाते, तो गरीबी तो 1971 में हट जानी चाहिए थी। इसीलिए Chief Economic Adviser ने अपने बजट में यह लिखा कि इन तीन क्षेत्रों में अभी और भी बहुत काम बाकी है, यह वास्तविकता है। हम हवा में नहीं जी रहे हैं और जब मैं यह कह रहा हूं कि हम हवा में नहीं जी रहे हैं, I was wondering to myself when this illustration is given that in the Chief Economic Advisor you have very good doctor but you have a terrible patient. Let me tell you, even if there is a bad case and if you have a good doctor, he will probably end up curing the patient. What do we do for those ten years from 2004 to 2014 when you had a terrible doctor? When you have a terrible doctor, even the healthiest patient is likely to disappear!

After this entire smug approach, I was trying to analyse. You see, during the boom period, the whole global economy was doing well. When, in 2011, we started facing challenges, honestly analyse what it is that you left behind. I am now going to give you six or seven sets of data. I will immediately yield if you correct me on a single one of these as mistake. Let us start with 2012. Why I am starting with the GDP in 2012 is because prior to 2012, the old series was applicable. So, it is unfair to compare old series with the new series.

**SHRI ANAND SHARMA:** Will you release the numbers for ten years under the old series and the new series?

**SHRI ARUN JAITLEY:** I am releasing. Since a number of questions were put to me, data gives the answer to each one of them.

(Contd. by KLS/3L)